मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को टैगोर इंटरनैशनल स्कूल में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान, के 62वें प्रांतीय अधिवेशन में सम्मिलित हुये। मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

'गहलोत सरकार ने संसाधनों के बिना ही कॉलेज खोलने जैसे दिशाहीन फैसले किए'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान, के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में कहा

- **शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन टैगोर इंटरनैशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में किया गया था।**
- **मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब हमारी सरकार ने इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी गठित की है। यह कमेटी कॉलेज की फीज़बिलिटी व औचित्य का परीक्षण करेगी।**
- **मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि, कॉलेज एवं युनिर्वसिटी में रिक्त पद भरने की कार्यवाही जल्दी ही शुरु की जाएगी।**
- **अधिवेशन को उप मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आर.एस.एस. के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम मुख्य वक्ता थे।**

जयपुर, 21 जून (का.सं.)। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, पिछली सरकार ने जल जीवन मिशन, बिजली खरीद और बिना किसी संसाधनों के महाविद्यालय खोलने जैसे दिशाहीन गलत फैसले लिए सरकार उन सभी फैसलों को रिव्यू करेगी। जल जीवन मिशन में जहां पानी के स्रोतों के बिना ही टंकी बना दी गई। वहीं बिजली खरीद में हजारों करोड़ का घाटा किया गया। महाविद्यालय खोलने के संबंध में भी बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के अंधाधुंध महाविद्यालय राजसेस के तहत खोल दिए गए। जिनमें कोई स्थाई शिक्षक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार ने राजसेस के अंतर्गत खोले गए इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इन सभी कॉलेजों की फीज़बिलिटी एवं औचित्य का परीक्षण कर आगे कार्यवाही करेगी।

शर्मा शुक्रवार को टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (उच्च शिक्षा) के 62वें प्रांतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं तथा उनके विचारों का समाज पर गहरा प्रभाव होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारतीयता से ओतप्रोत संगठन है, जो कि देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने का कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि, राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेशवासियों को शिक्षा का बेहतर वातावरण देने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्पित है।

शर्मा ने कहा कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाएगी।

समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि, शिक्षक युवाओं में ज्ञान, कला कौशल में वृद्धि करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशलपरक रोजगार को बढ़ावा देने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा भावी चुनौतियों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि, 350 वर्ष पूर्व ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक नए सूर्य का उदय हुआ था। बर्बरता और उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदुओं को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए शिवाजी महाराज ने हिंदू पदपादशाही की स्थापना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी स्थापना 100 वर्ष पूर्व हुई, हिंदुओं का संगठन है। यह संगठन विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए तत्पर है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के एन गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश-भक्त संगठन के रूप में विश्व में पहचान की बात कही। कार्यक्रम में भाग संचालक मानसिंह चौहान भी मंच पर उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व निंबाराम ने माधव बस्ती स्थित पार्क में 5 पौधे रोपित किए।

इस अवसर पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ए.बी.आर.एस.एम.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जे.पी. सिंघल, महामंत्री (राजस्थान) डॉ. सुशील कुमार बिस्सु, अध्यक्ष (राजस्थान) डॉ. दीपक शर्मा, आयोजक सचिव डॉ. कमल किशोर मिश्रा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेन्द्र कपूर, प्रदेश संगठन मंत्री घनश्याम, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के राजस्थान प्रांत के क्षेत्र प्रचारक निंबाराम सहित बड़ी संख्या में संगठन के लोग मौजूद थे।

सी.एस.आई.आर.-यू.जी.सी. नेट परीक्षा स्थगित की गई

नैशनल टैस्टिंग एजेन्सी (एन.टी.ए.) ने संसाधनों की कमी के चलते 25, 26, व 27 जून को होने वाली परीक्षा बाद में कराने का फैसला किया

- **इस साल, कुल 11.21 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।**
- **गौरतलब है कि, इससे पहले बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने, यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट - यूजीसी-नेट जून 2024, की परीक्षा को भी रद्द कर दिया था। इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भी अनियमितताएं देखने को मिली थीं।**

नई दिल्ली, 21 जून। नैशनल टैस्ट एजेंसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सी.एस.आई. आर.-यू.जी.सी. नेट की 25, 26, 27 जून को होने वाली परीक्षाएं संसाधनों की कमी के कारण स्थगित करने की बात कही गई है। एग्जाम की नई डेट जल्द ही नेशनल टेस्ट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। अधिक जानकारियों के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक साइट पर विजिट कर सकते हैं। गौरतलब है कि सीएसआईआर-यूजीसी नेट जून 2024 कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी) मोड में 25, 26 और 27 जून को आयोजित की जानी थी। इस साल, कुल 11,21,225 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।

सी.एस.आई.आर.-यू.जी.सी. नेट परीक्षा पैर्टन- इस पेपर का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहता है। परीक्षा 180 मिनट या तीन घंटे के लिए आयोजित की जाती है और पेपर में मल्टीपल चॉइस प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। परीक्षा में पांच पेपर होते हैं: रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान, जीवन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान।

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सी यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा को भी रद्द कर दिया था। इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भी अनियमितताएं देखने को मिली थी।

भारतीय सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत नवंबर 2017 में स्थापित राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) एक स्वायत्त निकाय है जिसे कई प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने का काम सौंपा गया है। एजेंसी की अध्यक्षता एचआरडी मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् करते हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं।एनटीए एनईईटी, जेईई, सीटीईटी, गेट, जीपैट, जीमैट, कैट और यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाएं आयोजित करता है।

सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर की पात्रता के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता यूजीसी-नेट के पेपर-1और पेपर- 2 में उम्मीदवार की परफॉर्मेंस के आधार पर तय होती है। जो उम्मीदवार केवल सहायक प्रोफेसर पद के लिए क्वालीफाई करते हैं, उन्हें इसके बाद सहायक प्रोफेसर बनने के लिए संबंधित यूनिवर्सिटी, कॉलेजों या राज्य सरकारों के भर्ती नियमों का पालन करना होता है।

चीन के नये राजदूत ने दिल्ली में वामपंथी नेताओं से मुलाकात की

नई दिल्ली, 21 जून। भारत में चीन के नए राजदूत शू फीहोंग ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा नेता डी राजा से मुलाकात की। पिछले महीने भारत में चीन के दूत के रूप में कार्यभार संभालने वाले फीहोंग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दोनों वामपंथी नेताओं के साथ बैठकों की तस्वीरों को साझा किया।

- **चीन के नवनियुक्त राजदूत शू फीहोंग ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा नेता डी राजा से मुलाकात की।**

फीहोंग ने कहा कि उन्हें दोनों नेताओं से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के साथ चीन-भारत संबंधों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। माकपा और भाकपा के सूत्रों ने इस बैठक को चीनी राजदूत के साथ शिष्टाचार भेंट बताया।

कैनडा की..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहना है कि, कैनडा, अलगाववादियों और भारत-विरोधी तत्वों का गढ़ बन रहा है।

'कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जल्द हासिल होगा'

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि, कश्मीरियों के लिए विधानसभा चुनाव कराने की तैयारियां शुरु हो गई हैं

- **प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, अब वह दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे।'' उन्होंने कहा, ''वह दिन भी जल्द ही आएगा जब एक राज्य के रूप में जम्मू-कश्मीर अपने लिए बेहतर भविष्य बनाएगा।''**

नई दिल्ली, 21 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा।

श्रीनगर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (एसकेआईसीसी) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। इस दौरान पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों का भी जिक्र किया और कहा कि शांति के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वह दिन दूर नहीं जब जम्मू-कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे।" उन्होंने कहा, "वह दिन भी जल्द ही आएगा जब एक राज्य के रूप में जम्मू-कश्मीर अपने लिए बेहतर भविष्य बनाएगा।" प्रधानमंत्री गुरुवार शाम को श्रीनगर पहुंचे और एस.के.आई.सी.सी. गए, जहां उन्होंने विभिन्न स्टार्ट-अप द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में 1,500 करोड़ रुपये की 84 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार पाने वाले 2,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में लोकतंत्र का झंडा बुलंद करने के लिए "लोगों का व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद" करने के लिए कश्मीर आए हैं।

उन्होंने कहा, "आज सुबह जब मैं श्रीनगर आने की तैयारी कर रहा था, तो मैं बहुत उत्साहित था। जब मैंने सोचा कि मैं इतना उत्साहित क्यों हूं, तो मेरे दिमाग में दो कारण आए - एक तीसरा कारण भी है, जो यह है कि मैंने यहां लंबे समय तक काम किया है और बहुत से लोगों से मेरा परिचय हुआ है। एक कारण जम्मू-कश्मीर की विकास परियोजनाएं थीं और दूसरा यह कि संसदीय चुनावों के बाद यह मेरी आपसे पहली बातचीत थी। आपने लोकतंत्र को जीत दिलाई। आपने पिछले 35-40 सालों के सभी (मतदान के) रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह दर्शाता है कि यहां के युवाओं का लोकतंत्र में गहरा विश्वास है। मैं लोगों को धन्यवाद देने के लिए कश्मीर घाटी आना चाहता था।

केजरीवाल रिहा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैण्डर्स से प्राप्त फण्ड्स का उपयोग गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनाव प्रचार अभियान को फायनैंस करने में किया गया। केजरीवाल गोवा चुनाव के संयोजक थे।

राजू ने जोर देकर कहा कि निचली अदालत का निर्णय गलत तथ्यों और तिथियों पर आधारित है जिसमें दुर्भावना प्रकट होती है। उन्होंने वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि जमानत मंजूर किए जाने के निर्णय सभी प्रासंगिक तथ्यों के विस्तृत मूल्यांकन पर आधारित होने चाहिए।

अरविन्द केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने ई.डी. की चुनौती पर पलटवार करते हुए कहा कि "ये तर्क सही नहीं है। विस्तृत बहस हुई है, क्या सात घंटे की जिरह पर्याप्त नहीं है? किसी चीज़ को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए।"

केजरीवाल को ई.डी. ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के तहत हुए मनी लॉण्डरिंग के केस में गिरफ्तार किया था। यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल की आपत्ति के बाद रद्द कर दी गई थी।

भारी हड़कम्प...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि, प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस के प्रति कितनी ज्यादा कटुता और असहयोग की भावना है और इससे स्पष्ट है कि विपक्षी दलो के प्रति प्रतिशोध की भावना कायम रहेगी।

प्रधानमंत्री स्पीकर की पोस्ट भाजपा के पास ही रखेंगे और डिप्टी स्पीकर का पद किसी सहयोगी दल को दे देंगे। वे विपक्ष को कुछ भी देना नहीं चाहते है।

अठारहवीं लोकसभा सहजता से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि अब विपक्ष की सीटें बढ़ गई हैं और वह भाजपा को मनमाने तरीके से काम नहीं करने देगा, जैसा कि अब तक होता रहा है। सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटैम स्पीकर बनाने की परम्परा का पालन 1956 में नहीं किया गया था तब सरदार हुकुम सिंह को प्रोटैम स्पीकर बनाया गया था। सन् 1977 में डी.एन. तिवारी को प्रोटैम स्पीकर बनाया गया था, वह भी वरिष्ठतम सांसद नहीं थे।

अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरु होगा और 24 व 25 जून नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे। स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं

नई दिल्ली, 21 जून (वार्ता)। बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर शुक्रवार शाम यहां पहुंचीं। शेख हसीना की यह एक माह में नयी दिल्ली की दूसरी यात्रा है। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगी और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। प्रधानमंत्री शनिवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री का नयी दिल्ली के इंदिरागांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर स्वागत किया। भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भी प्रधानमंत्री हसीना का हवाई अड्डे पर स्वागत करने के लिए उपस्थित थे।

मंत्रालय ने कहा, बंगलादेश भारत का एक प्रमुख साझेदार और भरोसेमंद पड़ोसी है। शेख हसीना की इस यात्रा से इस प्रतिष्ठित द्विपक्षीय साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कई आमंत्रित गणमान्य विदेशी नेताओं के साथ हसीना भी गत नौ जून को दिल्ली आयी थीं।

हज यात्रियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्वास्थ्य मंत्रालय को स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेवारियाँ दी गई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि, करीब 1,75,025 लोग हज के लिए गए, जिनमें से 40,000 लोग 60 वर्ष के ऊपर के बुजुर्ग शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि, इस वर्ष के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने आगे कहा "हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इससे हमें अपनी सेवाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने बताया कि एक लाइव पोर्टल डवलप किया गया है जिसमें उन यात्रियों का रियल टाइम डेटा व विश्लेषण मिलता रहता है जिन्हें मैडिकल केयर की ज़रूरत है।

बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पद से इस्तीफा दिया

नई दिल्ली, 21 जून। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। खुद अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें टी.एम.सी. कैंडिडेट युसूफ पठान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी, जो पूर्व में क्रिकेटर रहे हैं। कांग्रेस की बंगाल यूनिट ने शुक्रवार को एक मीटिंग भी बुलाई। इस मीटिंग में चुनाव नतीजों को लेकर बात हुई।

एक सवाल यह भी उठा कि वामपंथी दलों के साथ गठजोड़ करने का फैसला ऊपर से थोपा गया। इसके लिए जमीनी स्तर के नेताओं और राज्य के बड़े नेताओं को भी भरोसे में नहीं लिया गया। चुनाव नतीजों की समीक्षा वाली मीटिंग में जिलाध्यक्षों ने गठबंधन को लेकर चिंता जताई और कहा कि इसके लिए राय नहीं ली गई। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी खुद सीपीएम के साथ गठबंधन के पक्ष में रहे हैं। कहा जाता है कि वह उत्तर बंगाल और खुद अपने जिले में कांग्रेस की स्थिति मजबूत रखने के लिए सीपीएम का सहारा लेते हैं। इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक गुलाम अहमद मीर से राज्य के नेताओं ने अपनी चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि सीपीएम के साथ गठजोड़ में दक्षिण बंगाल का ध्यान नहीं रखा गया। जिलाध्यक्षों की बात को भी नहीं सुना गया। इन नेताओं का कहना था कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में सी.पी.एम. (कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी) के साथ गठजोड़ को लेकर नाराजगी है।

- **चर्चा है कि, अधीर रंजन के कहने पर ही कांग्रेस-सी.पी.एम. गठबंधन हुआ था, जिसे पार्टी नेता बंगाल में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण मान रहे हैं।**

फॉरैंसिक लैब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया था कि जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर, 2020 को आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक आयु सीमा में माना जाएगा। याचिका में कहा गया कि, राज्य सरकार की इस अधिसूचना के बावजूद भी इस भर्ती में याचिकाकर्ता को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है। आयु सीमा के अलावा याचिकाकर्ता भर्ती में नियुक्त होने की सभी पात्रता पूरी करता है। ऐसे में उसे कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत आयु सीमा में छूट दिलाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने और भर्ती को याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखा है।

तमिलनाडू की भांति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को खत्म करने पर विचार कर रही है।

"हम तमिलनाडू सरकार की राह पर चलने पर विचार कर रहे हैं। हम नीट का विरोध कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ा घोटाला है।

हमारे लोगों ने प्रदेश में संस्थानों का निर्माण किया है परन्तु वे अपने समुदाय से संबद्ध विद्यार्थियों को इनमें सीटें उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। हमें इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करने की जरूरत है।"

पहले राज्य सरकार को अधिकार था या कहें कि वह मैडिकल कॉलेज में एडमीशन में राज्य सरकार की चलती थी। परन्तु जब से नीट लागू हुई है यह विशेषाधिकार राज्य सरकार से छीन लिया गया है, खासकर तब सरकार चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को चला रही है और कुछ मैडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में भी हैं।

कर्नाटक भी इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहता है और खासतौर से नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने के व परीक्षा प्रक्रिया के आयोजन में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद नीट के खिलाफ देशव्यापी उपजे सख्त आक्रोश का फायदा उठाना चाहती है। बिहार पुलिस पहले ही परीक्षा सम्पन्न होने से पूर्व नीट के कुछ परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों द्वारा नीट के प्रश्न पत्र "खरीदने" के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है।

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमिलनाडू में सेवानिवृत न्यायाधीश ए.के. राजन की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पाया है कि नीट ने तमिलभाषा माध्यम वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को फेल किया है और यह नुकसान उन विद्यार्थियों को हुआ है जो गरीब परिवारों के थे।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि नीट सी.बी.एस.ई. सिलैबस वाले विद्यार्थियों के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है और उनके लिए अच्छा है जो पैसे खर्च करके अतिरिक्त प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं।

आयोग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रदेश में नीट के कोचिंग सैन्टरों का उद्योग 5,750 करोड़ रूपए तक पहुंच चुका है।

यह बात कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर है कि तमिलनाडू की विधानसभा ने एक विधेयक सर्वसम्मति से नीट पर प्रतिबंध को लेकर पारित किया था परन्तु सरकार ने इस बिल को मंजूरी नहीं दी और विधानसभा को वापस भेज दिया। वर्ष 2022 में तमिलनाडू विधानसभा ने इस बिल में बगैर कोई बदलाव किए पुन: पारित कर दिया ताकि तमिलनाडू में नीट पर रोक लगाई जा सके।

नई राजनीतिक परिस्थितियों में आज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्लैब्स थे।

इन्हें ज़ीरो प्रतिशत स्लैब के अलावा केवल 3, 12 और 28 प्रतिशत के त्रिस्तरीय स्लैब्स में एक तर्कसंगत स्वरूप देना था। इसके अलावा गुड्स एण्ड सर्विसेज़ के सभी टैक्सेज़ को मूल प्रस्ताव के अनुसार टैक्स के दायरे में लाना था और उनमें कोई क्रमिक छूट भी नहीं दी जानी थी। पूरे देश के लिए एक टैक्स व्यवस्था विकसित करने में पूर्ण स्पष्टता का होना संभव नहीं था, क्योंकि एक सिंगल मार्केट की अवधारणा किसी अर्थशास्त्री के मन की एक आदर्श स्थिति ही साबित हुआ।

कार्यरूप में, जी.एस.टी. दरों के स्ट्रक्चर से महंगाई बढ़ गई क्योंकि कुछ चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं को शून्य दर कैटेगरी में रखा जाना था, फिर भी जी.एस.टी. लागू होने के बाद इसकी वर्तमान व्यवस्था में छह से अधिक दरें है। इसके बावजूद तीन मुख्य वस्तुएं ज़र्दा, पैट्रोलियम और शराब जी.एस.टी. सिस्टम के दायरे से बाहर हैं।

इस सिस्टम के रेट स्ट्रक्चर को लेकर एक अनैच्छिक स्वीकारोक्ति है, लेकिन किसी ना किसी दिन ये रेट्स तर्कसंगत और कम हों जाएगी, किन्तु ऐसा कब होगा, ये भविष्य के गर्भ में हैं।

पैट्रोलियम का ही उदाहरण लीजिए। केन्द्र सरकार इस पर कुछ शुल्क लगाती हैं और राज्य सरकारें अपना सरचार्ज, जिससे इसकी कीमत आयातित कीमत से भी अधिक हो जाती हैं। कोई ये तर्क भी दे सकता है कि पैट्रोलियम की कठोर कीमतें अच्छी हैं क्योंकि ऐसा होने पर उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती।

राज्य सरकारें इन सामानों पर कर निर्धारण की शक्तियों को छोड़ना पसंद नहीं करती हैं क्योंकि, उनके लिए ये कुछ ही क्षेत्र बचे हैं, जहां से वे कुछ अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं क्योंकि, बाकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, आखिरकार, वो अपने कर निर्धारण के अधिकारों को छोड़ चुकी है।

जी.एस.टी. शुरु होने के बाद, सच में कुछ उल्लेखनीय लाभ हुए हैं। देश का खंडित बाजार एक हो गया है। अब एक ट्रक को हर राज्य की सीमा पर रुककर, निरीक्षकों और अन्य से निपटना नहीं पडता है। पहले उन्हें हमेशा घूस देनी पड़ती थी।

हमने एक देश, एक कर का मूल उद्देश्य हासिल कर लिया है। लेकिन समय आ गया है कुछ बुनियादी पुनर्विचार और तंत्र को बदलती हुई जरुरतों के अनुसार और ज्यादा सुधार करने का।

अब जबकि हमारे पास एक राजनीतिक व्यवस्था होगी तो, बेहतर वित्तीय संरचना के लिए एक ज्यादा लाभकर केन्द्र -राज्य सहकारी संघवाद का अमल किया जा सकता है।

मतदाता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जम्मू कश्मीर में इस वर्ष के अंत तक चुनाव होने हैं।

आयोग ने कहा कि संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन से पूर्व इनकी समीक्षा की जाएगी। इसमें घर-घर जाकर एक से ज्यादा प्रविष्टियां व मृत मतदाताओं की जानकारी एकत्रित कर मतदाता सूची में सुधार किया जाएगा। साथ ही वोटर आई.डी. में मतदाता का साप सुथरा फोटोग्राफ लगा हो यह भी सुनिश्चित किया जाएगा।

घर-घर जाकर वैरिफिकेशन की प्रक्रिया 25 जून से शुरु होकर 24 जुलाई तक चलेगी। इलैक्टोरल रोल का प्रकाशन 25 जुलाई को होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600